

बीडा की बसावट का रास्ता साफ

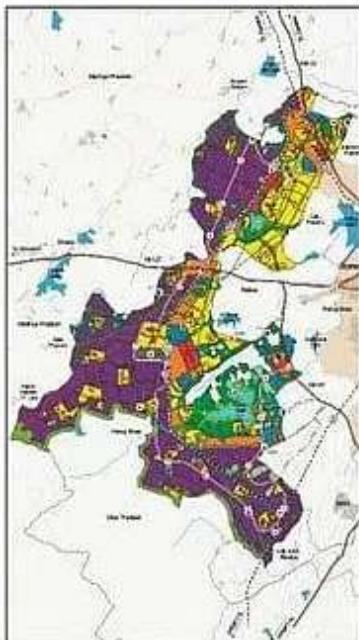
आठ माह बाद मास्टर प्लान तैयार, 30 दिनों तक दाखिल की जा सकेंगी आपत्तियां



अमर उजाला ब्यूरो

झांसी। आठ महीने लंबी कवायद के बाद बीडा का ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार हो गया। शुक्रवार को इसका सार्वजनिक प्रकाशन कर दिया गया। प्रस्तावित मास्टर प्लान में सर्वाधिक 38.8 फीसदी स्थान उद्योगों के लिए सुरक्षित रखा गया जबकि आवासीय इकाइयों के लिए 15.2 फीसदी स्थान तय किया गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन, सड़क, रेल, शैक्षिक संस्थान समेत सार्वजनिक सुविधाओं के लिहाज से भी बीडा में स्थान तय किया गया है।

बुंदेलखण्ड औद्योगिक विकास प्रधिकरण (बीडा) के लिए कुल 35 हजार हेक्टेयर जमीन प्रस्तावित है। इसका भू-उपयोग तय करने का काम सिंगापुर की एजेंसी सुरबाना जुरांग को सौंपा गया था। यिछले आठ महीने के दौरान कंपनी ने डोन सर्वे करके पूरे क्षेत्र का भू-सर्वेक्षण किया। डोन सर्वे के जरिए पूरे इलाके की मैपिंग हुई। इसके आधार



यह है मास्टर प्लान।

पर यह मास्टर प्लान तैयार हुआ है।

मास्टर प्लान में खास तौर से उद्योगों के लिए स्थान तय किया गया है। बीडा अफसरों के मुताबिक, मास्टर प्लान में आठ श्रेणी में लैंड यूज को विभाजित किया गया है। उद्योगों के लिए सर्वाधिक जगह 35.8 फीसदी (90.58 वर्ग किलोमीटर) रखा गया है। पर्यावरण के लिए ग्रीन ब्लैट भी तैयार होगा। बिजली, सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के लिए

प्रस्तावित प्रमुख क्षेत्रफल

श्रेणी	वर्ग किलोमीटर	प्रतिशत
उद्योग	90.58	38.8
आवासीय	38.39	15.2
ग्रामीण आवासीय	5.11	2
व्यावासायिक	3.92	1.5
मिश्रित उपयोग	13.01	5.1
प्रतिष्ठान	9.39	3.7
जनसुविधाएं	1.01	0.4
ग्रीन ब्लैट	26.93	10.6
ग्रीन बफर	25.69	10.1
रोड एवं रेल	25.56	10.5
लॉजिस्टिक	1.55	0.6
जलाशाय	7.13	2.8
कुल	253.33	100

खोले जाएंगे 20 थाने समेत नौ फायर स्टेशन

बीडा में 20 थानों समेत नौ फायर स्टेशन के लिए भूमि प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित मास्टर प्लान में एक पुलिस लाइन, दो होमगार्ड ऑफिस समेत एक-एक डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर एवं फायर ट्रेनिंग सेंटर के लिए स्थान तय किया गया है।

जगह तय की गई है। 15 कॉलेज समेत एक विश्वविद्यालय कैंपस को भी जगह दी जाएगी। दो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी मास्टर प्लान में प्रस्ताव है।

ओएसडी सौम्य मिश्रा के

मुताबिक, प्रस्तावित मास्टर प्लान का सार्वजनिक प्रकाशन कर दिया गया है। एक माह तक आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। इन आपत्तियों की सुनवाई के बाद यह मास्टर प्लान अंतिम रूप से तय होगा।